

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर०ए०एस०

राजस्व अपील संख्या 66/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. दरियाव कंवर बेवा बाघसिंह जाति राजपूत निवासी धणी तहसील बाली		1. फतेहसिंह पुत्र मोतीसिंह 2. भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी धणी तहसील बाली 3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति :
श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

--: निर्णय ::--

दिनांक : 26-11-18

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरुद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 97/2014 फतेहसिंह बनाम भंवरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से दुर्भिसंधि करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसमें जैर अपील वादस्थ भूमि में स्वयं का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा होना बताया। उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में नियत करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की। वास्तविक स्थिति यह है कि जैर अपील विवादित आराजी पूर्व में दौलतसिंह की खातेदारी भूमि थी। दौलतसिंह के दो पुत्र थे, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता मोतीसिंह तथा



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दूसरे अपीलाण्ट के पति बाघसिंह थे। इस प्रकार जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा आता है तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। मोतीसिंह व उसके वारिश्मान द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि शांतिलाल पुत्र खीमाराम को बेचान किया जा चुका है, जो कालान्तर में शांतिलाल द्वारा प्रताप पुत्र रणजीतसिंह को बेचान की जा चुकी है। इसके बावजूद भी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा विधि विरुद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत कर विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट उपस्थित ही नहीं हुई, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा होने के इन्द्राज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरुद्ध है। प्रकरण में जारी प्राथमिक डिक्री की जो पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है, वह भी विधि अनुसार नहीं है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को ही तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रेसित कर दिया, जबकि विधि अनुसार तहसीलदार को मौका निरीक्षण कर पक्षकारान् की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, जो नहीं किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व मौके अनुसार तैयार नजरी नक्शा से विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही राजस्व लोक अदालत में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। हस्तगत निर्णय लोक अदालत के तहत पारित किया गया है, जिसकी अपील अनुज्ञेय नहीं है। जिस भूमि पर अपीलाण्ट ने स्वयं का कब्जा काशत होना बताया है, विभाजन में वही भूमि उनके हिस्से में रखी गई है। जहां जिस पक्षकार का कब्जा है, उसी के अनुसार हिस्से में जितनी भूमि आती है, तदनुसार विभाजन की डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। तहसीलदार द्वारा नियमों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो अपीलाण्ट की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में निर्णित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में खातेदारान् का हिस्सा अंकित नहीं है। उक्त भूमि के विधिक विभाजन हेतु रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा अपीलाण्ट के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, उस



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नोटिस को रेस्पोजेन्ट संख्या 2 की उपस्थिति में चस्पा किया जाना अंकित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्यक् तामील माता है। जहां तक तामील की विधिमान्यता का प्रश्न है, तो इस प्रकार की तामील के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों को रेखांकित किया जाना आवश्यक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 17 के अनुसार — जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया — जहाँ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहाँ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहाँ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था।

आदेश 5 नियम 19 — तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा — जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहाँ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सम्मन किन दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के समक्ष आबाद मकान पर चस्पा किया गया, अंकित ही नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तामीली को पर्याप्त माना है, जो विधि से परे है। इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करने हेतु जो नोटिस जारी किए, वे अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट्स को संयुक्त रूप से जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है — "Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण-रूपेण चस्पा होता है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा न ही तहसीलदार द्वारा मौका



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निरीक्षण ही किया गया, जबकि विभाजन के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 में सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान निम्न प्रकार है - S..20 of RAJASTHAN TENANCY (Revenue Board) Rules, 1955 - 20 DIVISION OF HOLDING BY DECREE.

Same as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding the distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided the following principles shall be observed:-

(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding.

(b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible.

(c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land.

(d) As far as possible, existing fields shall not be split up.

(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall, as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

Division of Holding by Agreement or by Order of Court"

नियम 21 में नक्शा बनाना और उपविभाजित खेतों का अंकन करने का प्रावधान इस प्रकार है कि तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग-अलग रंगों से दिखाया जायेगा और किसी खेत को उपविभाजित किया गया है, तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार ही नहीं किया गया, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल की मुख्य पीठ द्वारा आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में निम्न अभिमत प्रकट किया है -

Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, Rules 18 to 21 - Reference - Preparation of proposal for division by Tehsildar - Question for consideration is whether under Rules 18 to 21 of Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may sub-delegate his administrative power in respect of preparation of proposal for division - Held, it is mandatory for Tehsildar that he himself inspect site and prepare proposal for division of holdings - He may entrust ministerial work to its subordinate Naib Tehsildar, ILR or Patwari etc., for preparation of map and demarcation of sub-divided field and filing of colours - Imperative upon Tehsildar that he himself prepare report under his seal and signature, he can not forward report prepared by ILR, Patwari and draftsman without application of his mind - Directions to SDO to ensure that report submitted before him prepared by Tehsildar as per law and if report not prepared by Tehsildar himself then SDO to return it to Tehsildar for preparation of report - Direction to Registrar, Board of Revenue to send copy of judgment to all concerned for compliance and action.



(Handwritten signature)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपरोक्त न्याय निर्णय से यह स्थिति प्रकट होती है कि नियम 18 से 21 में जो प्रावधान प्रदत्त है, उसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार ही अधिकृत है, जिसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव न तो तैयार किया गया एवं न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित होने से समर्थन योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sub-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order can be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 97/2014 फतेहसिंह बनाम भंवरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 एवं 22.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908




राजस्व अपील प्राधिकार
पाली

के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार पृथक पृथक विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली